

# अनुगामिनी

दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब बनेगा 'कर्तव्य पथ' 3 फडणवीस बोले- उद्घव को सत्ता से हटाने की आखिरी लड़ाई 8

## शिक्षा और शिक्षकों के प्रति नजरिया बदलने का समय आ गया है : सीएम

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 05 सितम्बर ।

सिविकम सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मनन केंद्र में 'निःपुण भारत, निःपुण सिक्किम' के बैनर तले राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके अलावा आयोजन में मुख्यमंत्री की धर्मपती श्रीमती कृष्णा राई, शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा के अलावा कैबिनेट मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष सांगे लेखचा, सांसद इंद्र हांग सुब्बा, मुख्य सचिव वीबी पाठक, सलाहकार, विधायक, विभागीय अधिकारी और शिक्षकों की भी विशेष उपस्थिति रही।

इस अवसर पर अपने उद्घाटन वक्तव्य में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर तेलंग ने सिविकम के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दृष्टिकोण, मिशन एवं कार्यों की प्रस्तुति देते हुए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन हासिल करने की दिशा में चुनौतियों पर प्रकाश डाला। वहाँ कार्यक्रम को सम्पूर्णाधित करते हुए शिक्षा मंत्री केएन लेञ्चा ने कहा कि बच्चों के सर्वार्थीनियत विकास हेतु देश के शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे ध्यान



में रखते हुए ही 2026-27 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करने के लक्ष्य के साथ नयी शिक्षा नीति 2020 को लाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने निःपुण भारत, निःपुण सिक्किम के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि शुरुआती स्तर पर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों के क्षमता निर्माण, हरेक बच्चे की प्रगति हेतु उच्च गुणवत्ता के संसाधन मुहैया कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।

वहाँ कार्यक्रम को सम्पूर्णाधित करते हुए तमांग ने अपने शिक्षकों के विभिन्न व्यापक विधायकों को बधाई दी।

(गोले) ने अपने शिक्षक जीवन को याद करते हुए कहा कि अपने पूर्व विद्यार्थियों को आज विभिन्न सम्मानजनक पदों पर देखकर गर्व होता है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक तथा सेकेंडरी स्तर पर शिक्षा की बेहतरी हेतु कई कदम उठाये गये हैं। उनके अनुसार शिक्षा और शिक्षकों के क्षमता निर्माण, हरेक बच्चे की प्रगति हेतु उच्च गुणवत्ता के संसाधन मुहैया कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।

वहाँ कार्यक्रम को सम्पूर्णाधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने शिक्षकों के विभिन्न व्यापक

बावजूद, शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान सरकार की विभिन्न शिक्षा और शिक्षकों के प्रति बदले हुए रूपये को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रीय पुस्तकों से सम्मानित शिक्षकों को विदेश दौरे पर भेजा जाएगा। वहाँ अपने सम्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री तमांग ने उन सभी शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने समाज में शिक्षा के प्रसार हेतु अपना बलिदान दिया है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्वर्गीय डा सर्वपल्ली

राधाकृष्णन को याद करते हुए उनके योगदान पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने अपने छात्र जीवन को भी याद किया, जब वह हमेशा 5 सितम्बर को अपने शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु तप्त पर रहे थे।

इस अवसर पर राज्य के छह जिलों के प्राथमिक एवं सेकेंडरी स्तर के 11 शिक्षकों को राज्य सम्मान और 28 शिक्षकों को सराहना प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। वहाँ समारोह में नई दिल्ली में शिक्षक दिवस समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किये जाने वाले राज्य के दो शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की गयी। इनमें मॉडन एसएसएस की श्रीमती माला जिगदल दोरजी और एकलव्य मॉडल आवासी स्कूल के सिद्धार्थ योग्यन शामिल हो रहे। दोनों को राष्ट्रीय द्वारा सम्मानित किया गया। वहाँ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से ताशी नामायाल अकादमी को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गयी।

वहाँ इस दौरान सिक्किम स्टेट एजुकेशन सर्विस केंटर, सिक्किम टीचर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ हेस ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड सिनियर सेकेंडरी स्कॉल्स की ओर से मुख्यमंत्री गोले को सम्मानित किया गया।

वन इंकारी फाल्स के ठेका को लेकर विवाद नियमों को ताक पर रखकर दिया गया ठेका : कला राई



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 05 सितम्बर ।

राजभासी नीति के खिलाफ धरने के रूप में देखा जा सकता है।

पार्षद कला राई ने धरना देने के बाद और मंत्री बीएस पंथ और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के बाद कहा कि हमें पता चला कि संबंधित विभाग ने एक व्यक्ति को इसके संचालन का काम देने जन्म ले लिया है। आरोप लगाया गया है कि पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के दो शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की गयी। इनमें मॉडन एसएसएस की श्रीमती माला जिगदल दोरजी और एकलव्य मॉडल आवासी स्कूल के सिद्धार्थ योग्यन शामिल हो रहे। दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

महिला नेता हैं और इसे उनकी सरकार की नीति के खिलाफ धरने के बाद कहा है कि हमें पता चला कि फॉल्स के संचालन का काम उसे सौंपा गया है। उन्होंने अन्य लोगों को इसके संचालन का काम देने की मांग की है। 2019 से बंद इस पार्क के संचालन हेतु मंत्री बीएस पंथ और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के बाद कहा है कि हमें पता चला कि संबंधित विभाग ने एक व्यक्ति को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराधिकारी ने इसके विरोध में हम धरने पर बैठ गए। इसके कुछ देर के बाद हमें बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि बनझाकरी फॉल्स पर्यटन स्थल की तब तक बंद रखा जाए। जब तक कि नई खुली निविदा नहीं आरंभित की जाती है। उन्होंने कहा कि हम साइट के संचालन की अनुमति नहीं देंगे और हम चाहते हैं कि नई खुली निविदा एवं निष्पक्ष गति है।

इस मामले में मंत्री बीएस पंथ ने दावा किया कि सभी प्रिंकियाओं को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराधिकारी ने इसके संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी जो पहले से ही अपील हैं और हम चाहते हैं कि इस साइट से गरीबों को एक मौका मिले।

कला राई ने बताया कि नियमों की अनदेखी कर किसी एक व्यक्ति को फॉल्स पर्यटक की जगह खाली निविदा का अधिकारी है। उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी कर किसी एक व्यक्ति को फॉल्स पर्यटक की जगह खाली निविदा का अधिकारी है। उनके अनुसार अब इस सम्बंध में सरकार की फैसला ले सकती है।

## समाज निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण : राज्यपाल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 05 सितम्बर ।

शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज सिक्किम आईसीएफआई यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया गया।

विश्वविद्यालय के एनजे यशस्वी सभागार में आयोजित हुए इस समान समारोह में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके अलावा समारोह में राज्य विधायक में 45 शिक्षकों को राज्य सम्मानित किया गया। इसके दौरान शिक्षकों के दो शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने यह शिक्षकों को बधाई दी।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में राज्यपाल गंगा प्रसाद ने उनके जनरल विनियमों के अन्य विधायिका के रूप में उपस्थित थे। उनके अलावा समारोह में राज्य विधायिका के दो शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने यह शिक्षकों को बधाई दी।

जनाने का उपयुक्त अवसर है। उन्होंने उपस्थित सभी शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान जताया।

इससे पहले ओआईसी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के अतिरिक्त निरेश एनएस सिद्धैया ने विश्वविद्यालय और एसटीपीआई के बीच हुए समझौते के बारे में बोलते हुए कहा कि शोध एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उनके इस समझौते से स्टार्ट-अप समुदायों एवं औद्योगिक हितधारकों को फॉल्स डाला गया। उन्होंने बताया कि पिछले दो दशकों से आईटी एवं आईटीईएस द्व्यांगों में स्टार्ट-अप्स को सहयोग देने तथा नवीकरणीकी विधायिका की विधायिका को विश्वविद्यालय के बीच समझौते पर विवाद नहीं है। उनके अनुसार अब इस सम्बंध में सरकार की फैसला ले सकती है।

## शिक्षक दिवस पर चर्चा व सम्मान समारोह आयोजित



अनुग

## नितिन गडकरी का खुलासा : खराब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सङ्केत हादसों के लिए जिम्मेदार

नई दिल्ली, 05 सितम्बर (एजेन्सी)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कुछ सङ्केत दुर्घटनाओं के लिए त्रुटिपूर्ण परियोजना रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कंपनियों को राजमार्गों एवं अन्य सङ्केतों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बास्ते उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

सङ्केत परिवर्तन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार नवी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। खुलकर विचार व्यक्त करने के लिए विष्वात गडकरी ने कहा, कंपनियों द्वारा तैयार की गई कुछ डीपीआर अत्यधिक खराब हैं और सङ्केत दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

'उन्होंने डीपीआर तैयार करने वाली कंपनियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। गडकरी ने कहा, 'शुरुआत वहां (डीपीआर) से करो। अगर वो (कंपनी) नहीं सुधरेंगी, तो पूरा तुम्हारा स्थानाश हो जाएगा।'

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आगर कोई अनाड़ी चालक हो तो नवी मरिंडीज कार भी समस्या खड़ी कर सकती है। गडकरी ने सङ्केत परियोजनाओं में देरी के कारणों की पहचान करने पर जो दिया व्यक्तिकों देरी के कारण निर्माण की बढ़ती लागत भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। यद्य पांस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिक्सी की रविवार को एक सङ्केत दुर्घटना में तब मौत हो गई जब उनकी कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में डिवाइडर से टकरा गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड व्यरों के अंकड़ों के अनुसार, 2021 में पूरे भारत में सङ्केत दुर्घटनाओं में 1.55 लाख से अधिक तोपों की जान चली गई। इस तरह औसतन रोजाना 426 या हर घंटे में 18 लोगों की मौत हुई जो अब तक किसी भी कैलेंडर वर्ष में दर्ज सर्वाधिक मौत का आंकड़ा है।

## शीर्ष कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- सरकार पर नहीं डाल सकते निजी अस्पतालों की सुरक्षा का भार

नई दिल्ली, 05 सितम्बर (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी अस्पतालों की सुरक्षा से जुड़ी एक याचिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एएस आमों होम और चिकित्सा संस्थान निजी हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार से ये आशा नहीं की जा सकती कि वे इन निजी संस्थानों को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। पीठ ने ये भी कहा कि निजी अस्पतालों को अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध इंतजाम करने चाहिए।

पीठ दिल्ली में डिकल एसोसिएशन और इंडियन मेंडिकल एसोसिएशन की असम राज्य शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यजीत बोरा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि अधिकारियों को अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में याचिका पर मीठे पाठ जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर किसानों को कृषि पंच सेटों में मीटर लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि देश के सभी को इनकार करते हुए एस के कौल और न्यायमूर्ति एएस आमों होम और चिकित्सा संस्थान निजी हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार से ये आशा नहीं की जा सकती कि वे इन निजी संस्थानों को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। पीठ ने ये भी कहा कि निजी अस्पतालों को अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध इंतजाम करने चाहिए।

अदालत की फटकार के बाद याचिकाकर्ताओं के बकील ने कहा कि वे अपनी याचिका में जरूरी संपोषण के बाद संबंधित दस्तावेज जमा करेंगे। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि इसमें विवरण का अधार है। सच्च ही पीठ ने आगे कहा कि आगे भी हम इस तरह की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने कहा कि हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद नहीं कर सकते जो कि व्यावसायिक उद्यम है।

**कुछ लोग कोर्ट केस कर सरकारी भर्तियों को रोकने की दे रहे धमकी : सीएम ममता**

कोलकाता, 05 सितम्बर (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि सरकार स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार देने की इच्छुक है, लेकिन अदालती मामलों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है।

शिक्षक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने एसएससी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से बात की और कहा कि लोगों का एक वर्ग जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर-करके सरकार को भर्ती रोकने की धमकी दे रहा है।

पार्थ चर्टर्जी की गिरफतारी के मामले में आलोचनाओं का सामना कर रही नहीं मिलते ने कहा कि कई बार जो सत्ता के शीर्ष पायदान पर होते हैं, उन्हें निचले स्तर के लोगों के द्वारा किप्पे का खुदाव दिया जाता है। यह एक व्यक्तिगत विचार के तहत जनता की सेवा कर रही है, 'हर दिन उपहास' किया जा रहा है।

बनर्जी ने कहा कि टीएमसी शासन के 11 वर्षों के दौरान एसएससी द्वारा अबतक 2.63 लाख शिक्षण और गैर-शिक्षण भर्तियों की गई हैं और 10,000 से अधिक

## जम्मू कश्मीर में गांधीवादी मूल्यों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताएं की जाएंगी आयोजित: उपराज्यपाल

श्रीनगर, 05 सितम्बर (एजेन्सी)। जम्मू कश्मीर के प्रतियोगिता शुरू करेंगे। गांधी जयंती पर, हम सभी पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और देश के सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रमुख गांधीवादीयों को एकत्र करेंगे, ताकि महात्मा गांधी के मूल्य (वैल्यू) कितावें तक ही समाप्ति न रहे बल्कि हमारी नैतिकता और चरित्र में भी प्रतिविवित हों।

उन्होंने कहा कि हाल में अंतकावादीयों द्वारा शिक्षकों की हत्या करने की घटनाएं हुई हैं।

उपराज्यपाल ने कहा, 'कुछ समय पहले कुछ लोगों ने निर्दोष शिक्षकों की हत्या का जयन्त्र अपराध किया है। सुक्षम बल अपना काम कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि अब समझ आ गया है कि समाज ऐसे अपराधों के खिलाफ खड़ा हो। जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का बहुत खून बहाया गया है। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो



कम से कम इसकी निंदा तो कर ही सकते हैं।

वह उन घटनाओं का हवाला दे रहे थे जिनमें पिछले साल शहर के ईदगाह इलाके में एक स्कूल में दो शिक्षकों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में कुलगाम जिले में एक अन्य शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

## के सीआर ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- 2024 में आएगी गैर भाजपा सरकार तो किसानों को मिलेगी फ्री बिजली

हैदराबाद, 05 सितम्बर (एजेन्सी)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को बढ़ा गलान किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एक गैर-भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वे निजामाबाद में जिला कार्यालय परिसर और टीआरएस पार्टी के जिला मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस जनसभा में उन्होंने भाजपा सरकार और आपूर्ति पाठी के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थान निजी हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार से ये आशा नहीं की जा सकती कि वे इन निजी संस्थानों को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। पीठ ने ये भी कहा कि निजी अस्पतालों को अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध इंतजाम करने चाहिए।



कुनैंगों तो उन्हें तेलंगाना की तरह मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो किसानों सहित सभी को 24 घंटे बिजली प्रदान करता हो। उन्होंने कहा कि देश में तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्रत्येक दिलित परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड के बाद एक राज्य नहीं है जो बिकानी दोलों को बांटती है और सरकारों को गिराने के लिए खोती करना मुश्किल बना रही है। बोर्ड की उपरान्त एसएससी नौकरी के लिए खोती करना आसान है।

इस दौरान के सीआर घोषणा करते हुए कहा कि इस देश के लिए लड़ाई तेलंगाना से शुरू होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने एनपीए के दौरान 12 लाख कोरेड रुपये के क्रूप को देखा था। उन्होंने कहा कि देश में तेलंगाना को मुफ्त बिजली देने को तैयार नहीं है, जिस पर 1.45 लाख कोरेड रुपये खर्च होंगे।

इस दौरान के सीआर घोषणा करते हुए कहा कि कृष्ण के लिए लड़ाई के दौरान उन्होंने कहा कि बोर्ड की जीर्णता नहीं है जो बिकानी दोलों को बांटती है और सरकारों को गिराने के लिए खोती करना मुश्किल बना रही है।

कर्ज नहीं है। उन्होंने कहा, 'केंद्र हमें धन नहीं देता है और बंगाल की वित्तीय स्थिति की तुलना में आपूर्ति की जाएगी।' उन्होंने कहा कि देश में तेलंगाना एक राज्य है जो बिकानी दोलों को बांटती है और सरकारों को गिराने के लिए खोती करना मुश्किल बना रही है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत य











## शाह ने दिया मिशन-135 का नारा, फडणवीस बोले- उद्धव को सत्ता से हटाने की आखिरी लड़ाई



मुंबई, 05 सितम्बर (एजेन्सी)। वृहत्मुंबई महानगर पालिका चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी में जुटी है। ऐसे में मुंबई पहुंचे बीजेपी की चुनावी रणनीति के 'चाणक्य' और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएमसी चुनाव को लेकर प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी के लिए मिशन-135 का नारा दिया। वहाँ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार का बीएमसी चुनाव को लेकर प्रमुख नेताओं के साथ देवेंद्र फडणवीस के घर सागर बंगले पर बैठक की। यहाँ अमित शाह ने मुंबई बीएमसी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नेताओं को 227 सीटों में से 135 सीटें जीतने का योगेष्ट दिया। दरअसल बीएमसी चुनाव सिंतंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य बीएमसी का कंट्रोल शिवसेना से छीनकर अपने हाथों में लेना है।

इस दौरान अमित शाह ने सभी कार्यकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीएमसी चुनाव की तैयारी में एक प्रशासक की नियुक्ति होने तक बीएमसी पर शिवसेना का कंट्रोल था। बीएमसी की सत्ता पिछले 25 साल से शिवसेना के कब्जे में है। शिवसेना में फूट के बाद बीजेपी इस बार बीएमसी की सत्ता शिवसेना से छीनने के लिए इस बार कुशल रणनीति के तहत मेहनत कर रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार की रात को मुंबई पहुंचे। गणेशोत्तम के दौरान अमित शाह

सोमवार को गणपति दर्शन के बाद बीएमसी चुनाव को लेकर प्रमुख नेताओं के साथ देवेंद्र फडणवीस के घर सागर बंगले पर बैठक की। यहाँ अमित शाह ने मुंबई बीएमसी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नेताओं को 48 घंटे में जवाब देने को कहा गया। जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल ने 'आप' विधायकों व नेताओं को लोगल नोटिस भेजा है। 'आप' नेताओं को लोगल नोटिस भेजा है। आप नेताओं को इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने को कहा गया।

दरअसल बीएमसी चुनाव सिंतंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य बीएमसी का कंट्रोल शिवसेना से छीनकर अपने हाथों में लेना है। बीएमसी चुनाव करने में देवेंद्र के कारण इस साल की शुरुआत में एक प्रशासक की नियुक्ति होने तक बीएमसी पर शिवसेना का कंट्रोल था। बीएमसी की सत्ता पिछले 25 साल से शिवसेना के कब्जे में है। शिवसेना में फूट के बाद बीजेपी इस बार बीएमसी की सत्ता शिवसेना से छीनने के लिए इस बार कुशल रणनीति के तहत मेहनत कर रही है। उन्होंने एकान्थ शिंदे गुरु के साथ चुनाव लड़ने पर जोर दिया। बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने

**कांग्रेस के 3 विधायकों को मिली झारखंड लौटने की सशर्त अनुमति**

कोलकाता, 05 सितम्बर (एजेन्सी)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों को राज्य में लौटने की सशर्त अनुमति दी, जिन्हें जुलाई में भारी मात्रा में बंकदी के साथ पश्चिम बंगाल में गिरफतार किया गया था, ताकि वे अपने मूल राज्य में लौट सकें।

न्यायमूर्ति जयमाला बागची और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि तीन विधायकों को राज्य में लौटने की सशर्त अनुमति दी, जिन्हें जुलाई में भारी मात्रा में बंकदी के साथ पश्चिम बंगाल में गिरफतार किया गया था, ताकि वे अपने मूल

राज्य में लौट सकें।

आपको बता दें कि 30 जुलाई 2022 की शाम को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के रानीहाटी में विधायकों को बैंक नोटों के बैग के साथ पकड़ा गया था। नोटों की गिनती की गई तो कुल राशि 48 लाख रुपये निकली।

ये तीनों विधायक दो अन्य सहयोगियों के साथ एक एसयूवी में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने आपको बताया कि एसयूवी को राज्य परिवहन के लिए केवल झारखंड विधानसभा सत्र में उपस्थित होने की अनुमति के लिए प्रार्थना की।

उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी अपील को सशर्त मंजूरी दे दी।

खुफिया सूचनाओं के आधार

**बंगाल के स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक चरित्र निर्माण पर नया अध्याय : ममता बनर्जी**

कोलकाता, 05 सितम्बर (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के स्कूली पाठ्यक्रम में जल्द ही नैतिक चरित्र निर्माण' पर एक नया अध्याय शामिल किया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भ्रात्याचार के कई अरोपी से घिरी हुई है।

उन्होंने शिक्षक दिवस पर सोमवार की दोपहर में शिक्षक सम्मान समरोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इस मौके पर राज्य के शिक्षक मंत्री ब्रत्य बसु मौजूद थे और उन्होंने इस संबंध में तैयारी की प्रक्रिया तकाल प्रभाव से शुरू करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण व्यापार भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से नहीं जाना जाता, जिसका वह मालिक है। किसी के पास किसान पैसा है, यह किसी व्यक्ति की एकाम्र पहचान नहीं है। हमेशा याद रखें कि आज जो पैसा आपके पास है वह कल नहीं हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की एकाम्र पहचान नहीं है। हमेशा याद रखें कि आज जो पैसा आपके पास है वह कल रास्ता अपनाते हैं।



उन्होंने कहा, 'मैं इमानदार रहना चाहता हूं, यह केवल मुझ पर निर्भर करेगा। सभी उंतलियां एक जैसी नहीं होतीं। समाज में अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी। इसलिए कुछ बुरे लोगों के लिए पूरे समाज को बदलना चाहता हूं।' उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर चल रहे विवाद को बहुत पहले सुलझाया जा सकता था, यदि इस मामले में लगातार जनहित याचिका (पीआईएल) द्यावर नहीं की गई होती।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'ये कानूनी अड़बने पूरी प्रक्रिया में देरी कर रही हैं। मैं मानती हूं कि कुछ गलतियां हुई थीं, लेकिन कम से कम हमें उन्हें सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए।'

उन्होंने आरोप लगाया, 'पिछले वाम मोर्चा शासन के दौरान सत्ताधारी सभी कागजात और दस्तावेजों को नष्ट कर देते थे।'

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक : नूतन वर्मा द्वारा प्राइटर्स, प्रिमुला कॉर्टेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रत्ना निवास, मेट्रो प्लाइट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।

सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com

## एलजी ने 'आप' नेताओं को भेला लीगल नोटिस, फेक व्यूज फैलाने का आरोप

नई दिल्ली, 05 सितम्बर (एजेन्सी)। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सरकार ने कथित जूहे आरोप लगाने के मामले में संजय पाठक द्वारा राजीव डिजाइनिंग का नाम शामिल है।

'आप' नेताओं ने विनय कुमार सरकार के लिए गहरा जांच की जाती है।

जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल ने 'आप' विधायकों व नेताओं को लोगल नोटिस भेजा है। एलजी की ओर से इस नोटिस में 'आप' नेताओं के ऊपर फेक व्यूज फैलाने और उनकी बेटी शिवांगी सरकार के लिए दबाव दिल्ली की ओर से इस नोटिस में अपने कार्यवाले को दौरान कथित रूप से प्रतिवर्भवित नोटों को बदलने का आरोप लगाया था।

जानकारी के अनुसार विधायकों व नेताओं को लोगल नोटिस भेजा है।

शनिवार को एक और नया आरोप

लगाया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल सरकार ने केवीआईएस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और एक खादी लाउंज की इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका अपनी बेटी शिवांगी सरकार को दिया गया।

'आप' ने इसे सरकार द्वारा

प्रैतिक्रिया नोटों को बदलने का आरोप

लगाया था।

जानकारी के अनुसार विधायकों व नेताओं को लोगल नोटिस भेजा है।

शनिवार को एक और नया आरोप

लगाया था कि अगले दिन विधायकों व नेताओं को लोगल नोटिस भेजा है।

शनिवार को एक और नया आरोप

लगाया था कि अगले दिन विधायकों व नेताओं को लोगल नोटिस भेजा है।

शनिवार को एक और नया आरोप

लगाया था कि अगले दिन विधायकों व नेताओं को लोगल नोटिस भेजा है।

शनिवार को एक और नया आरोप

लगाया था कि अगले दिन विधायकों व नेताओं को लोगल नोटिस भेजा है।

शनिवार को एक और नया आरोप

लगाया था कि अगले दिन विधायकों व